THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (PROF SHER SINGH) (a) to (c) Financial assistance to State Governments for welfare and rehabilitation of ex-servicemen, their dependents and war widows is given from Central Welfare Funds viz, Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of Ex servicemen and Post War Services Reconstruction Fund instituted for the purpose No scheme for rehabilitation of ex servicemen and war widows is financed directly from the Central Government Funds

2 There is a fund in each State corresponding to the Central Welfare Funds The State Funds have been established out of grants from the Central Funds The State Welfare Funds are augmented to the extent possible Requests from the State Governments for augmentation are accepted only if they make a watching contribution A statement showing the amounts given to each State Government during the last three years is given in Statement 'I laid on the Table of the House [*Placed in Library See* No LT 1161/77]

3 It has now been decided that the corpus of the funds is to be kept intact and that only the interest earned from the investment of the State Welfare Funds should be utilised in accordance with the objects of the funds

4 In addition the expenditure on the establishment and maintenance of Zila Sainik Boards is shared between the Centre and the State in the ratio of 50 50 A statement showng State wise allocation of funds for the maintenance of Zila Sainik Boards in the country, during the last three years is at statement 'II' laid on the Table of the House [*Placed in Library See* No LT 1161/77]

5 The basis for calculating the States' share for augmenting State Welfare Funds is the number of serving personnel in the Armed Forces recruited from the respective States/Union Territories on the first day of the year in which the allocation is made

दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1335. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली मे पुलिस कर्मचारियो ने हाल मे हडताल की थी , और

(ख) यदि हा तो उनकी माग क्या थी और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री घनिक लाल मडल) (क) तथा (ख) दिल्ली के पुलिस कर्मचारियो न हाल मे कोई हडताल नही की है । परन्तु दिल्ली पुलिस के चतुथ श्रेणी के कुछ कर्मचारी अपनी मागे मनवाने के लिए भूख हडताल पर थे जिनमे अन्य के बीच सघ का मान्यता प्रदान करना 8 घटे की पारी ड्यूटी, राजपत्रित छुट्टिया स्वीकृत करना, पूरी वर्दी सप्लाई करना और उनका पर्यवेक्षण नियत्रण दिल्ली पुलिस से दिल्ली प्रशासन को स्थानान्तरित करना शामिल है । आन्दोलन उप-राज्यपाल के इस आश्वासन पर समाप्त कर दिया गया था कि उनकी मागो पर विचार किया जाएगा ।

गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोग

1336 **श्री यज्ञदत्त शर्मा**
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा :
श्री नटवर लाल बी० परमार :
श्री युवराज :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगो के विकास के लिये योजना तैयार कर रही है ,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात् इन लोगों को प्रतिशतता में कितनी कमी आने की संभावना है ; और

(घ) मार्च, 1977 में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता क्या थी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : *(क) और (ख) . अगली योजना का प्रमुख* उद्देश्य होगा एक निश्चित समयावधि में बेरोजगारी को और काफी कुछ अल्प रोजगार को दूर करना और इस प्रकार गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगो के रहन-सहन के स्तर में पर्याप्त सुधार करना । जो विकास नीति परिकल्पित की गई है वह है—बढ़ी हुई सिचाई और उत्पादकता में सुधार करके कृषि मे अधिकाधिक श्रमिकों को लगाना और साथ ही साथ विकेन्द्रित लघु उद्योग तथा घरेलू उद्योग में रोजगार मे वृद्धि करना । संबंधित नीतियो और कार्यक्रमो तथा उपयुक्त निवेश नीतियों को 1978 से 1983 के लिए योजना प्रारूप मे विस्तार से दिया जाएगा ।

(ग) और (घ) . गरीबी के स्तर की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की जा सकती है । योजना आयोग की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तीसरी योजना की अवधि मे सुझाई गई परिभाषा के अनुसार, देश की लगभग 60 प्रतिशत जन-संख्या को 1973–74 में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाला माना जा सकता था । प्रोफेसर दांडेकर और प्रोफेसर रथ द्वारा 1971 में न्यूनतम पोषाहार की आवश्यकताओं आधार पर सुझाई गई गरीबी की वैकल्पिक परिभाषा के अनुसार, लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या को उसी वर्ष में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाला माना जाएगा । मार्च, 1977 में उपभोग के इन दो स्तरों से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता के कोई अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । इस समय यह बताना भी संभव नहीं है कि आने वाले वर्षों में ठीक-ठीक कितनी गरीबी क्रमिक रूप में कम होती जाएगी, परंतु यह आशा की जानी चाहिए कि योजनाबद्ध कार्य-क्रमों से अगली दो पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी बहुत कुछ कम हो जाएगी ।

छठी योजना में बड़े तापीय बिजलीघरों की स्थापना

1337. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में पांच बड़े तापीय बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों तथा किनकिन- राज्यों में स्थापित किए जायेंगे?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) और (ख) . देश में बढ़ते हुए विद्युत विकास के संदर्भ में भारत सरकार ने यह उचित समझा था कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सेक्टर में विद्युत उत्पादन करने के लिए पिट-हैडों पर सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना की जाए ।

उत्तर प्रदेश में सिंगरौली में प्रथम सुपर ताप विद्युत केन्द्र कार्यान्वयनाधीन है । अन्य प्रस्तावित चार स्थल निम्नलिखित है :—

(1) मध्य प्रदेश में कोरबा

(2) आन्ध्र प्रदेश में रामागुंडम

(3) तमिलनाडु में नेवेली

(4) पश्चिम बंगाल में फरक्का

गुजरात में बिजली की कमी

1338. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बिजली की कमी है ; और